भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1030

सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि

1030. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर हरियाणा राज्य में युवाओं में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए कया कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हरियाणा के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई रोजगार मेले आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान अब तक आयोजित रोजगार मेलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-2022 और 2022-23 के दौरान देश और हरियाणा में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:

(%)

वर्ष	अखिल भारतीय	हरियाणा
2021-22		
ग्रामीण	10.6	24.1
ग्रामीण+शहरी	12.4	23.3
2022-23		
ग्रामीण	8.0	16.6
ग्रामीण+शहरी	10.0	17.5

स्रोत: पीएलएफएस

उपरोक्त तालिका में आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के साथ-साथ हरियाणा में भी बेरोजगारी दर में पिछले कुछ वर्षों से गिरावट की प्रवृत्ति है।

राज्य रोजगार कार्यालय/मॉडल कैरियर केंद्र नियमित रूप से नौकरी मेलों का आयोजन करते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध में है।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 29.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आयोजित रोजगार मेलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**रोजगार मेला राज्य**	2023-2024
1	आंध्र प्रदेश	934
2	अरुणाचल प्रदेश	14
3	असम	79
4	बिहार	666
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ	210
7	दिल्ली	46
8	गुजरात	704
9	हरियाणा	72
10	हिमाचल प्रदेश	15
11	जम्मू एवं कश्मीर	240
12	झारखंड	459
13	कर्नाटक	323
14	केरल	154
15	मध्य प्रदेश	25
16	महाराष्ट्र	578
17	मणिपुर	10
18	मेघालय	48
19	मिजोरम	7
20	नागालैंड	19
21	ओडिशा	988
22	पुडुचेरी	65
23	पंजाब	451
24	राजस्थान	266
25	सिक्किम	12
26	तमिलनाडु	256
27	तेलंगाना	179
28	त्रिपुरा	17
29	उत्तर प्रदेश	1239
30	उत्तराखंड	65
31	पश्चिम बंगाल	237
अखलि भारत		8379

स्रोत: राज्य रोजगार कार्यालयों/मॉडल कैरियर केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार